बढ़ते बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली 12 जुलाई (ए)। आए दिन बैंक फ्रॉड की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) अक्सर आम लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से बचने की सलाह देता रहता है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बढ़ते घोटालों को रोकने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को एडवाइजरी जारी की है।क्या कहा बैंक नेबैंक ने अपने निर्देश में कहा है कि बैंकों में जमा और निकासी पर्चों को खाताधारक संभाल कर भरें। साथ ही चेक में किसी गलती के होने पर उस चेक को पूरी तरह से फाड़ दें या नष्ट कर दें। जिन शाखाओं में फ्रॉड हुआ है वे शाखाएं इसकी जानकारी दूसरे दिन अन्य शाखाओं को भी बताएं, फ्रॉड कैसे हुए, उनका मॉड्यूल क्या था, इसकी भी सूचना साझा करें। संबंधित बैंक स्टाफ को इस संबंध में जानकारी दें और अलर्ट पर रहें।

नेट न्यूट्रलिटी के फ्रे मवर्क को केंद्र ने मंजूरी दी

नई दिल्ली 12 जुलाई (ए)। सरकार नेट न्युट्रलिटी से जुड़े नियमों को शामिल करने के लिए टेलीकॉम लाइसेंसों में जल्द बदलाव करेगी। इन नियमों में कंटेंट को ब्लॉक करने या उसे सुस्त करने पर रोक लगाने का प्रावधान शामिल होगा। वहीं केवल अहम सेवाओं के लिए फास्ट लेन की इजाजत देने और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्कों को इनके दायरे से बाहर रखने का नियम भी इसमें शामिल किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में निर्णय करने वाली सबसे बड़ी इकाई टेलीकॉम कमीशन ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की नवंबर 2017 में दी गई सिफारिश बुधवार को पूरी तरह स्वीकार कर ली। इससे ओपन इंटरनेट को सपोर्ट करने के भारत के रुख को मजबूती मिलेगी। नेट न्यूट्रलिटी के सपोर्टरें ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि इससे इनोवेशन की गुंजाइश कम हो सकती है। कमीशन ने नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 को भी क्लियर कर दिया। इस पॉलिसी का मकसद रोजगार के मौके बनाना और साल 2022 तक 100 अरब डॉलर से ज्यादा इनवेस्टमेंट आकर्षित करना है। नई पॉलिसी को मंजूरी के लिए दो हफ्तों में कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने संवाददाताओं से कहा, नेट न्यूट्रलिटी पर ट्राई की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। नेट न्यूट्रलिटी पर बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, बशर्ते मामला क्रिटिकल सर्विसेज का न हो, जिसमें कुछ खास तरह के ट्रैफिक को प्राथमिकता देनी होती है। उन्होंने कहा, दूरसंचार विभाग आगे चलकर क्रिटिकल सर्विसेज की कैटेगरी नोटिफाई करेगा। इन सेवाओं को नेट न्यूट्रलिटी के बुनियादी सिद्धांतों के दायरे से अलग रखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही होता है। क्रिटिकल सर्विसेज के लिए अलग सिस्टम बनाया जाएगा। अरुणा ने कहा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी ओपन इंटरनेट के नियमों के तहत आएगा, लेकिन ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रिमोट डायग्नोस्टिक सर्जरी की जरूरत वाले हेल्थकेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज की कुछ खास श्रेणियों को सोशल मीडिया पर प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ऐसे संवाद में मिली-सेकेंड की देरी भी नहीं की जा सकती है।

प्रीमियम और ब्रिज-टू-लग्जरी सेगमेंट पर ई कॉमर्स कंपनियों की नजर

नई दिल्ली 12 जुलाई (ए)।फैशन और लाइफस्टाइल प्रॉडक्ट्स सेगमेंट में सफलता हासिल करने के बाद देश की ई-कॉमर्स कंपनियों की नजर अब प्रीमियम और ब्रिज-टू-लग्जरी सेगमेंट पर है। रिलायंस की एजियोडॉटकॉम ने पिछले कुछ महीनों में स्टीव मैडेन, डीसी शूज, एड हार्डी, गास, क्रिकसिल्वर, रॉबर्सी और सुपरड्राई जैसे कई ग्लोबल ब्रांड्स को अपने साथ जोड़ा है। फ्लिपकार्ट की जबॉन्गडॉटकॉम ने अपनी वेबसाइट पर लग्जरी प्रॉडक्ट्स के लिए जबॉन्ग स्टोर शुरू किया है, जिसके एक्सेस के लिए बायर्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। टाटा की सीएलआईक्यू भी अपनी वेबसाइट पर तेजी से नए प्रीमियम प्रॉडक्ट्स शामिल कर रही हैं। रिलायंस ब्रांड्स के चीफ एग्जिक्यूटिव दर्शन मेहता ने बताया कि 6,000 रुपये से ज्यादा के फैशन और लाइफस्टाइल प्रॉडक्ट्स के लिए देश में कुल मार्केट 1.5 करोड़ लोगों का है और यह मार्केट सालाना 20 पर्सेंट की दर से बढ़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए यह मार्केट काफी कम है। एक ई-कॉमर्स कंपनी के टॉप एग्जिक्यूटिव ने बताया कि फ्लिपकार्ट, मिंट्रा, एमेजॉन या जबान्ग समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैशन प्रॉडक्ट की औसत सेल 600 से 900 रुपये के बीच है। एग्जिक्यूटिव ने बताया, किसी भी प्रीमियम ब्रांड के प्रॉडक्ट की औसत कीमत 3,000 रुपये से ज्यादा है। ऐसे में ईकॉमर्स कंपनियों के लिए इन्हें बेचना काफी बड़ी चुनौती है। प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट काफी छोटा है। ऐसे में अगर कोई कंपनी सालाना 40-50 करोड़ के बिक्री का प्रयास करती है तो यह एक बड़ी सफलता होगी।

हालांकि टाटा सीएलआईक्यू का कहना है कि प्रीमियम ब्रांड्स उसके सेल्स में पहले ही योगदान दे रहे हैं। टाटा सीएलआईक्यू के चीफ एग्जिक्यूटिव विकास पुरोहित ने कहा, हम अच्छी कमाई कर रहे यंग लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। हम सालाना आधार पर 250 पर्सेंट से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं और भारत में हम जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर का हमारा बिजनेस में 8 से 12 पर्सेंट का योगदान है।% एजियो ने इस बारे में ईटी के भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।

जीएसटी : सस्ती हो सकती हैं ये चीजें और इनकी बढ़ सकती है कीमत

नई दिल्ली ,12 जुलाई (ए)। जीएसटी स्लैब पर 1 प्रतिशत सेस लगने वाला है। अगर ऐसा होता है तो लग्जरी चीजें महंगी हो जाएंगी। सरकार ने जीएसटी के तहत आने वाले इन आइटम्स पर सेस लगाने को मंजूरी दे दी है। यह सेस 28 फीसदी वाले स्लैब पर लगेगा। वहीं जीएसटी कांउसिल की 21 जुलाई को होने वाली बैठक में उन वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट घटाने पर विचार हो सकता है जिनसे सरकार के रेवेन्यू पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

सूत्रों के मुताबिक ऐसी वस्तुओं में सैनिटरी नैपकिन, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम शामिल हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सेवाओं पर टैक्स कम करने की मांग कर रही है। काउंसिल की अगली बैठक 21 जुलाई को होनी है। जीएसटी रेट पर फैसला जीएसटी काउंसिल ही करती है।

अभी सैनिटरी नैपकिन और ज्यादातर हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। नैपकिन पर टैक्स खत्म करने की मांग है। हैंडीक्राफ्ट बनाने के बिजनेस में छोटे कारोबारी ज्यादा हैं। इसलिए इन पर भी टैक्स घटाने या खत्म करने की मांग की जा रही है। वहीं 1 प्रतिशत सेस से लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे।

भारत एक भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार, तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने को हरसंभव कदम उठाएगा ईरान

नई दिल्ली12 जुलाई (ए)। भारत के तेल और ऊर्जा साझेदार रहे ईरान ने कहा है कि वह भारत को तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी हरसंभव कोशिश करेगा। उसने जोर देकर कहा है कि वह भारत का भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार रहा है। ईरान के दूतावास ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय दिया है जब उसके उप राजदूत ने मसूद रिजवानियन रहगी ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद यदि भारत ने ईरान से तेल आयात में कटौती की तो ईरान भारत को मिलने वाली विशिष्ट सहूलियतें बंद कर देगा। दूतावास ने कहा, वह अस्थिर ऊर्जा बाजार से निपटने में भारत को हो रही दिक्कतों को समझता है। उसने कहा कि ईरान द्विपक्षीय व्यापार विशेष तौर पर ईरानी तेल के आयात को बनाये रखने के लिए विभिन्न कदम उठाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा।रहगी ने बुधवार को कहा था कि यदि भारत ने सऊदी अरब, रूस, इराक, अमेरिका या किसी अन्य देश से तेल मंगाने की कोशिश की तो ईरान भारत को दी जाने वाली विशिष्ट सहूलियतें बंद कर देगा।

चाबहार बंदरगाह पर ईरान ने भारत के प्रति जताई नाराजगी:एक दिन पहले ही चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान ने भारत के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। ईरान ने आरोप लगाया था कि भारत ने उसके साथ वादाखिलाफी की है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह में वादे के मुताबिक निवेश नहीं करने पर भारत की आलोचना करते हुए ईरान ने कहा कि यदि भारत ईरान से तेल का आयात कम करता है तो उसे मिलने वाले विशेष लाभ खत्म हो सकते हैं। ईरान के उप राजदूत और चार्ज डि अफेयर्स मसूद रजवानियन रहगी ने कहा कि यदि भारत अन्य देशों की तरह ईरान से तेल आयात कम कर सऊदी अरब, रूस, इराक और अमेरिका से आयात करता है तो उसे मिलने वाले विशेष लाभ को ईरान खत्म कर देगा।उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाबहार बंदरगाह और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। यदि चाबहार बंदरगाह में उसका सहयोग और भागीदारी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है तो भारत को इस संबंध में तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए।

रिकॉर्ड लो से 1 यूनिट ज्यादा रहा सोलर ऑक्शन टैरिफ

बेंगलुरु 12 जुलाई (ए)। सोलर पावर के लिए हुए हालिया ऑक्शन में टैरिफ 92.44 प्रति यूनिट के रिकॉर्ड लो लेवल से 91 प्रति यूनिट से ज्यादा ऊपर आ गया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट के लिए जमीन की खरीदारी में आने आने वाली दिक्कतों के हिसाब से टैरिफ एडजस्टमेंट हुआ है। इतने ऊंचे टैरिफ की वजह पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से समय पर पेमेंट मिलने को लेकर डिवेलपर्स के बीच पनपी आशंका भी है। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी (PNEDA) ने मंगलवार को 1000 मेगावॉट कैपेसिटी के लिए सोलर ऑक्शन कराया था। उसके लिए विनिंग टैरिफ बढ़कर 93.48-3.55 प्रति यूनिट हो गया। यह हालिया सोलर ऑक्शंस में सबसे ऊंचा विनिंग टैरिफ है। यूपी में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले महीने कराए गए 275 मेगावॉट के सोलर ऑक्शन में विनिंग बिड 93.32 प्रति यूनिट रही थी। PNEDA ने हालिया ऑक्शन में राज्य के कई हिस्सों में प्रोजेक्ट लोकेशन डिस्ट्रीब्यूट किए।

जल्द महंगे होंगे लग्जरी प्रॉडक्ट्स, लगेगा 1 फीसदी सेस

नई दिल्ली 12 जुलाई (ए)। सरकार ने जीएसटी के तहत आने वाले लग्जरी आइटम्स पर एक फीसदी कृषि सेस यानी उपकर लगाने को हरी झंडी दे दी है। इन लग्जरी आइटम्स पर अभी 28 फीसदी जीएसटी लगता है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने लग्जरी आइटम्स पर एक फीसदी कृषि सेस लगाने पर मुहर लगा दी है। अब इसे ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के जरिए जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इसको लागू कर दिया है।क्यों उठाया सरकार ने यह कदमअभी जिन लग्जरी आइटम्स पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है, उनमें एयरकंडिसनर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पेंट, सीमेंट, रंगीन टेलीविजन, परफ्यूम, डिश, वैक्यूम क्लीनर, टू व्हीलर, कार, एयरक्राफ्ट, पान मसाला, सिगरेट और टोबैको प्रॉडक्ट्स शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह फैसला किसानों के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाने के बाद किया है। एमएसपी बढ़ाने से सरकार के खजाने पर करीब 15,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अगर सरकार इसको खुद उठाएगी तो इससे वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। यही कारण है कि अब कृषि सेस लगाने का फैसला किया गया है।सरकार ने हाल में धान, दाल, मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी लागत का डेढ़ गुना करने का फैसला किया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है।

यूएस की सबसे धनी सेल्फ मेड वूमन की लिस्ट में दो भारतीय महिलाओं ने बनाई जगह

नई दिल्ली 12 जुलाई (ए)। फोर्ब्स 2018 अमेरिका की सबसे धनी सेल्फ मेड वूमन की सूची में दो भारतीय मूल की महिलाओं ने जगह बनाई है। कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी एरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल 18वें स्थान पर रही है जिनकी 1.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति रही है। वह कंपनी की वर्ष 2008 से सीईओ हैं। वर्ष 2017 में इसका राजस्व 1.6 बिलियन डॉलर रहा था। फोर्ब्स ने बताया है कि उल्लाल के पास एरिस्टा के करीब पांच फीसद स्टॉक हैं

आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग कंपनी सिंटेल की सह संस्थापक नीरजा सेठी 21वें स्थान पर रही हैं। इनकी संपत्ति एक बिलियन डॉलर की

रही है। नीरजा ने अपनी पति भरत देसाई के साथ मिलकर वर्ष 1980 में इस कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी में करीब 23000 कर्मचारी हैं जिनमें से 80 फीसद भारत में कार्यरत हैं

इस सूची में पहले स्थान पर Diane Hendricks हैं। इनकी कुल संपत्ति 4.9 बिलियन डॉलर रही है। वहीं दूसरे स्थान पर 4.3 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ मारियन इल्च रही हैं। 3.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जुडी फॉकनर तीसरे पर, 3.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मेग विटमैन चौथे स्थान पर और जोहनल हंट 3.2 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पांचवे स्थान पर रही हैं। इस सूची में शामिल 60 महिलाओं की संयुक्त संपत्ति 71 बिलियन डॉलर रही है।

यह आकड़ा वर्ष 2017 से 15 फीसद ज्यादा है। इनमें से 24 महिलाएं बिलियनार हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बता दें कि शीर्ष 60 महिला उद्यमियों में से 14 का जन्म अमेरिका से बाहर हुआ है।

टीसीएस के बाद अब रिलायंस बनी 100 अरब डॉलर की कंपनी

नई दिल्ली। 12 जुलाई (ए)। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) के 100 अरब डॉलर (करीब 6.85 लाख करोड़ रुपये) की कंपनी बनने के बाद अब रिलायंस भी इस क्लब में शामिल हो गई है।

गुरुवार को शेयर बाजार में आई तेजी के बाद रिलायंस 100 अरब डॉलर की कंपनी बनने में सफल रही है और इसका बाजार पूंजीकरण करीब 6.89 लाख करोड़ रुपये हो गया। करीब 12.15 बजे सेंसेक्स में कंपनी का शेयर 4.89 फीसद की बढ़त के साथ 1087 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, टीसीएस का शेयर 0.33 फीसद की कमजोरी के साथ 1972.20 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

रिलायंस ने अक्टूबर 2007 में पहली बार 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप का आंकड़ा पार किया था। उस समय डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 39.5 के स्तर पर था। रुपये में बात करें तो उस समय कंपनी की मार्केट कैप 4.11 लाख करोड़ रुपये थी। रिलायंस के 100 बिलियन डॉलर कंपनी बनने के बावजूद अधिकांश बोकरेज हाउस कंपनी के स्टॉक्स पर बुलिश नहीं है। मसलन, उनहोंने इसमें खरीदारी के लिए परहेज करने को कहा है। जेफरीज ने इस स्टॉक को 'होल्ड' से डाउनग्रेड कर 'अंडरपरफोर्म' कर दिया है।जिसके लिए 790 रुपये का टार्गेट प्राइस रखा है। 23 अप्रैल को ज़ुल्फ़ बनी थी 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप की भारतीय कंपनी23 अप्रैल को टीसीएस एकलौती भारतीय लिस्टेड कंपनी बनी थी जिसकी मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर हो गई थी। टीसीएस ने एक्सचेंज की मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया था। उस समय एक्सचेंज की मार्केट कैप 9800 करोड़ डॉलर के स्तर पर थी। टीसीएस 2500 करोड़ की कंपनी वर्ष 2010 में बनी थी। उसके बाद 50,000 करोड़ का आंकड़ा इसने वर्ष 2013 में और 7500 करोड़ 2014 में पार कर लिया था। जिसने अप्रैल में कुल 17.6 लाख बैरल प्रति दिन कच्चे की आपूर्ति की। इतना ही नहीं अमेरिकी कंपनियां जुलाई तक भारत को 1.5 करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल की सप्लाई करेंगी। यह इस लिहाज से अहम है क्योंकि पिछले साल अमेरिका ने भारत को कुल 80 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया था। अमेरिकी दबाव में भारत की तरफ से ईरान से होने वाली कच्चे तेल की खरीदारी को लगातार कम किए जाने का असर भारत-ईरान संबंधों पर भी दिखने लगा है।ईरान ने चेताया न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ राजनयिक ने भारत को चेताते हुए कहा है कि अगर ईरान के कच्चे तेल को भारत सऊदी अरब, रूस और अमेरिका से होने वाली सप्लाई से रिप्लेस करने की कोशिश करता है

कनॉट प्लेस दुनिया की नौवीं सबसे महंगी ऑफिस लोकेशन

नई दिल्ली 12 जुलाई (ए)।ऑफिस लोकेशन के किराये के मामले में देश की राजधानी के दिल में बसे कनॉट प्लेस का साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की प्रॉपर्टी सलाहकार कंपनी सीबीआरई के नवीनतम सालाना सर्वे में सबसे महंगी ऑफिस लोकेशन के मामले में कनॉट प्लेस एक पायदान ऊपर चढ़कर दुनियाभर में नौवें स्थान पर पहुंच गया है।सीबीआरई के मुताबिक कनॉट प्लेस में ऑफिस के लिए सालाना किराया 153 डॉलर (10,250 रुपये) प्रति वर्गफुट पर जा पहुंचा है। पिछले साल इस सूची में कनॉट प्लेस 10वें स्थान पर था। दिलचस्प यह है कि सीबीआरई के सालाना 'ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट्स' सर्वे के मुताबिक मुंबई के नरीमन प्वाइंट 'सेंट्रल बिजनेस डिस्टिक्ट' (सीबीडी) के अलावा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स (बीकेसी) की रैंकिंग फिसली है और दोनों का किराया घटा है सीबीआरई की सूची में सालाना 306.57 डॉलर प्रति वर्गफुट किराये के साथ हांगकांग (सेंट्रल) पहले स्थान पर है। वहीं, ब्रिटेन का लंदन (वेस्ट एंड) दूसरे, चीन का बीजिंग (फाइनेंस स्ट्रीट) तीसरे, हांगकांग में ही कोलून चौथे और बीजिंग (सीबीडी) पांचवें स्थान पर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क (मिडटाउन-मैनहट्टन) को सूची में महंगी ऑफिस लोकेशन के हिसाब से छठा और मिडटाउन-साउथ मैनहट्टन को सातवां स्थान मिला है। सीबीआई की सूची में जापान के टोक्यो (मुरुनीची/ओटेमाची) को आठवां और लंदन (सिटी) को 10वां स्थान मिला है।

वाहन बिक्री नए शिखर पर पहुंची

नई दिल्ल 12 जुलाई (ए)। देश में यात्री वाहनों की बिक्री में जून माह में 37.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यात्री वाहन क्षेत्र में करीब दस वर्ष में यह सबसे तेज मासिक वृद्धि है। हालांकि, वाहन बिक्री में हुई इस तीव्र वृद्धि के पीछे पिछले वर्ष के निचले आधार को प्रमुख वजह माना जा रहा है। पिछले साल जुलाई में जीएसटी लागू होने की प्रतीक्षा में खरीदारों ने कीमतें कम होने की उम्मीद में वाहन खरीद की अपनी योजना टाल दी थी। भारतीय वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने कहा कि घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री जून महीने में 37.54 प्रतिशत बढ़कर 2,73,759 इकाई हो गयी जबकि इससे पिछले वर्ष जून में 1,99,036 यात्री वाहनों की ही बिक्री हुई थी।यह यात्री वाहन क्षेत्र की दिसंबर 2009 के बाद की सबसे तेजी वृद्धि है। दिसंबर में यात्री वाहन बिक्री में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जून माह में कारों की बिक्री 34.21 प्रतिशत बढ़कर 1,83,885 वाहन रही, जो जून 2017 में 1,37,012 वाहन थी। सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने कहा कि पिछले वर्ष इसी अवधि में लोगों ने वाहन खरीदने की योजना टाल दी थी क्योंकि उन्हें जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें कम होने की उम्मीद थी। इसलिए इस वर्ष हम जो वृद्धि देख रहे हैं वो पिछले वर्ष हुई कम बिक्री के आधार पर हैपछले माह विशिष्ट उपयोगी वाहनों, कारों और वैन की बिक्री में क्रमश ~ 47.11 प्रतिशत, 34.21 प्रतिशत और 35.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाहीवाहन19.91प्रतिशतबढ़कर 8,73,501 इकाई रही, जो अप्रैल-जून 2017 में 7,28,483 इकाई थी। सियाम द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून 2018 में दुपहिया वाहनों की कुल बिक्री 22.28 प्रतिशत बढ़कर 18,67,884 इकाई रही जबकि जून 2017 में 15,27,509 दुपहिया वाहनों की

यूआईडीएआई ने कहा, भारत ने आधार का इस्तेमाल कर बचाए 90000 करोड़ रूपये

नई दिल्ली 12 जुलाई (ए)। यूआईडीएआई के अध्यक्ष जे. सत्यनारायण ने कल कहा कि भारत ने आधार को उपयोग में लाकर अब तक 90,000 करोड़ रुपये बचा लिए हैं। डिजिटल पहचान पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि औसतन लगभग तीन करोड़ लोग आधार का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से राशन, पेंशन, ग्रामीण रोजगार, छात्रवृत्ति में हुआ है। बुधवार को शुरू हुए तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) ने किया है। सम्मेलन में आधार पर विशेष ध्यान दिया गया है

90,000 करोड़ रुपयों से यादा के राजस्व की बचत :सत्यनारायण ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, खाद्य एवं लोक वितरण, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों ने 90,000 करोड़ रुपयों से यादा के राजस्व की बचत या आय की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शासन तंत्र प्रौद्योगिकी के साथ लगातार प्रगति कर रहा है और इससे देश अदृश्य शासन की परिकल्पना की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में शोध कराने की जरूरत पर जोर दिया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए शोध की जरूरत: उन्होंने कहा,हमें अधिक कुशल बायोमेट्रिक तंत्र, आधार ईको तंत्र, नामांकन प्रक्रिया में सुधार, अपडेशन और प्रमाणीकरण, कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में कार्यान्वयन और धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग का उपयोग करने के लिए शोध करने की जरूरत होगी। भारत और विदेश के लगभग 150 शोधकर्ता कार्यक्रम में सम्मेलन का उद्देश्य आईएसबी में डिजिटल आइडेंटिटी रिसर्च इनीशिएटिव (डीरी) द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रदर्शन करना है। डीरी का शोध मुख्य रूप से आधार को ध्यान में रखकर तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ और नुकसान का पता लगाने पर निर्भर है।